भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1795

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

ऊपरी भद्रा परियोजना

1795. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हासन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के तारिकेरे और कादूर तालुकों (चिकमगलूर जिला) के सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए लक्षित 3388 करोड़ रुपए की ऊपरी भद्रा परियोजना के सिंचाई घटक की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत, समय-सीमा और लाभार्थियों (किसानों की संख्या और एकड़ भूमि) सहित इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को समय पर पूरा किए जाने और इस परियोजना में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इसमें किसी विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी हां, हालांकि, जल राज्य का विषय है इस कारण से सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, इनका कार्यान्वयन और वित्तपोषण का अधिदेश संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख): कर्नाटक सरकार द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना का क्रियान्यवन किया जा रहा है जो कि एक लिफ्ट सिंचाई योजना है। इस परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक के चिकमगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर और दावणगेरे सूखा प्रवण जिलों में सूक्ष्म सिंचाई से 5,57,022 एकड़ भूमि को सिंचाई प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से मौजूदा वाणी विलास सागर जलाशय के पानी में भी बढ़ोत्तरी होगी।

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2020 में परियोजना की पुन: संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 21,473.67 करोड़ रुपए (वर्ष 2018-19 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 74.26 लाख होने का अनुमान है। इस परियोजना को मार्च, 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग): परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ने की सूचना है। भद्रा जलाशय से अज्जमपुरा सुरंग तक जल उठाने का कार्य दो चरणों में पूरा होने और उसके उपरांत चित्रदुर्ग और तमकुर शाखा

नहरों तक जल पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिए जाने की सूचना है। इसके अतिरिक्त, इस समय, तुंग नदी से भद्रा जलाशय तक जल को दो चरणों में उठाने का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि वाणी विलास सागर जलाशय में वर्ष 2019-20 से पानी छोड़ा जा रहा है।

हालांकि, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया जाता है कि परियोजना का कार्य अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार किया जा रहा है और इसलिए सिंचाई के किसी अतिरिक्त क्षेत्रफल पर विचार नहीं किया गया है।

(घ): परियोजना के कार्यान्वयन सहित परियोजना के कार्य में पाई गई गलतियों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का निर्णय लेना पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकारक्षेत्र में आता है। हालांकि, कर्नाटक सरकार ने जानकारी दी है कि परियोजना में विलंब के मुख्य कारणों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की धीमी गति, भू-स्वामियों द्वारा मुआवजे की अधिक मांग और निधियों की आवश्यकता शामिल है। इसलिए, अधिकारियों का शिथिल रवैया सामान्यत: विलंब का कारण नही है।

*****